

प्रेषक,

एस0राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम देहरादून।
- 2- समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत,
उत्तराखण्ड।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 19 जुलाई, 2010

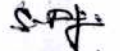
विषय:-नगर निकायों के अन्तर्गत सम्पत्ति कर को लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में नगर निकायों के अन्तर्गत सम्पत्ति कर को लगाये जाने हेतु व्यापक सुधार की आवश्यकता है जिस हेतु कर सुधार समिति के गठन की कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है।

2. अतः जब तक कर सुधार समिति द्वारा अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है और शासन द्वारा कर सुधार की प्रक्रिया तय नहीं हो जाती है, तब तक समस्त स्थानीय निकायों द्वारा वर्तमान में जो भी सम्पत्ति कर निर्धारित है उनकी वसूली की कार्यवाही पूर्व की भाँति ही की जाय एवं यदि किसी भी प्रकार की वृद्धि प्रस्तावित हो तो शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

भवदीय,



(एस0राजू)

प्रमुख सचिव।

संख्या 1232 / IV(2)-2010 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ✓ 4- निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को शहरी विकास विभाग के शासनादेशों में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(निधिमणि त्रिपाठी)

अपर सचिव।